



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ६, अंक (५)४]

सोमवार, जून २, २०१४/ज्येष्ठ १२, शके १९३६

[पृष्ठे ७, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २१

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २ जून २०१४ ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. XV OF 2014.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA ENTERTAINMENTS
DUTY ACT.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक १५ सन् २०१४।

महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम में अधिकतर संशोधन संबंधी विधेयक।

सन् १९२३ का महा १। **क्योंकि**, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने, महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिए, महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (जिसे इसमें आगे “ उक्त अध्यादेश ” कहा गया है) १० फरवरी २०१४ को प्रख्यापित किया था ;

सन् २०१४ का महा १। **और क्योंकि**, २४ फरवरी २०१४ को राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में बदलने के लिए एक विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा में सन् २०१४ का विधानसभा विधेयक क्र. २ के रूप में २४ फरवरी २०१४ को प्रस्तुत किया गया था ;

और क्योंकि, उक्त विधेयक राज्य विधानमंडल का २८ फरवरी २०१४ को सत्रावसान हो जाने के कारण राज्य विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सका था ;

और क्योंकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह की अवधि समाप्त होने के पश्चात्, अर्थात् दिनांक ६ अप्रैल २०१४ के बाद, प्रवर्तित होने से परिवर्तित हो जाएगा ;

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझा गया था ;

और क्योंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था; और, इसलिए, महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क (संशोधन और जारी रहना) अध्यादेश, २०१४, १० फरवरी २०१४ को प्रख्यापित हुआ था ;

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में एतद्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा
प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क (संशोधन और जारी रहना) अधिनियम, २०१४ कहलाये।
(२) यह १० फरवरी २०१४ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन १९२३ का १
की धारा २ के
१ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम (जिसे इसमें आगे “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा २ में, सन् १९२३ का १।
(एक) खण्ड (क-क१) के बाद, निम्न खण्डों की निविष्टि की जायेगी, अर्थात् :—

“(क-क २) “केबल ऑपरेटर” का तात्पर्य, केबल टेलिविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, सन् १९९५ की धारा २ के उपबंधों के अनुसार केबल ऑपरेटर के क्षेत्र में अधिसूचित क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत किये गये किसी व्यक्ति या कंपनी या बहुयंत्रणा ऑपरेटर से भी है और जो निवासी या अनिवासी स्थानों पर टेलिविजन सेटों के अंशदाताओं को फिल्में या चल चित्रपट या चल चित्रपटों की शृंखलाओं को प्रदर्शन के लिए पुनःप्रसारण डिजिटल टेलिविजन सिग्नल को संस्थापित करता है उससे है ;

(क-क ३) “स्थानीय केबल ऑपरेटर का तात्पर्य, किसी व्यक्ति या कंपनी से है, जो बहु-यंत्रणा ऑपरेटर से डिजिटल टेलिविजन सिग्नल स्वीकृत करता है और अंशदाताओं द्वारा अदायगी पर निवासी या अनिवासी स्थानों पर पुनःप्रसारण करता है ;”;

(दो) खंड (क-क) के बाद, निम्न खंड निविष्टि किया जायेगा :—

“(क-कख) “बहु-प्रणाली ऑपरेटर” का तात्पर्य, उस केबल ऑपरेटर से है जो प्रक्षेपक या उसकी अधिकृत एजेंसीओं से कार्यक्रम सेवाएँ प्राप्त करता है और उसकी स्वयं की कार्यक्रम सेवा में से पुनःप्रसारित या प्रसारित करता है, या तो साथ-साथ प्राप्ति द्वारा बहुउद्देशीय अंशदाताओं को सीधे या एक या एक से अधिक स्थानीय केबल ऑपरेटर से करता है और उसमें उसकी अधिकृत वितरण एजेंसियाँ सम्मिलित होंगी, चाहे जो भी नाम दो।”;

(तीन) खंड (ग) का उप-खंड (पाँच) अपमार्जित किया जायेगा।

सन १९२३ का १
की धारा ३ में
संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, विद्यमान उप-धारा ४, उसके खंड (क) के रूप में पुनःक्रमांकित की जायेगी और इसप्रकार पुनःक्रमांकित किये गये खंड (क) के बाद, निम्न खण्ड निविष्टि किया जायेगा, अर्थात् :—

“(ख) इस अधिनियम की उप-धारा २ में या किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वहाँ निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट दर पर मनोरंजन शुल्क राज्य सरकार को बहुउद्देशीय प्रणाली ऑपरेटर द्वारा अदा किया जायेगा। प्रति टेलिविजन सेट जो रेडिओ फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्राप्त करके फिल्मों के प्रदर्शन या चलचित्र चित्रपट या चित्रपटों की शृंखलाओं के साथ किसी भी प्रकार के अँटीना की सहायता से प्रदर्शन करता है या किसी अन्य उपस्कर से सुरक्षित प्रसारण के जरिये केबल नेटवर्क या केबल टेलिविजन संलग्न करता है या उसके जरिये इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलिविजन चलाता है।

(ग) स्थानिक केबल ऑपरेटर, कनेक्शन धारक से मनोरंजन शुल्क वसूल करेगा और समय के भीतर बहुउद्देशीय प्रणाली ऑपरेटर को उसे सौंप देगा जहाँ बहुउद्देशीय प्रणाली ऑपरेटर रजिस्ट्रीकृत है या सीधे राज्य सरकार को भुगतान करेगा। जहाँ बहुउद्देशीय प्रणाली ऑपरेटर रजिस्ट्रीकृत नहीं है तथापि मनोरंजन शुल्क, टेलिविजन सेटों पर उद्ग्रहित किया जायेगा जो निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट दरों पर पूर्व क्रियान्वित रेडिओ फ्रिक्वन्सी सिग्नलों और क्रियान्वित सेट टॉप बॉक्स के जरिए प्राप्त करता है।

(घ) खंड (ख) और (ग) के उपबंधों के अधीन, खंड (ख) और (ग) के अधीन देय मनोरंजन शुल्क के सुरक्षित उद्ग्रहण, वसूली और भुगतान के लिए बहुउद्देशीय प्रणाली ऑपरेटर या केबल ऑपरेटर, ऐसी सुरक्षित जमा और ऐसी सूचना जिला कलक्टर को जुटायेगा जैसा कि विहित किया जाये।”

४. मूल अधिनियम की धारा ५ में, “जुर्माना पाँच सौ रुपये से कम नहीं और एक हजार रुपये से अधिक नहीं” शब्दों के स्थान में, “जुर्माना प्रत्येक अधिकारी के लिए पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं या राजस्व हानि के पाँच गुना, जो भी अधिक हो शब्द रखे जायेंगे।” सन् १९२३ का १ की धारा ५ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा ७ में, खंड (ग) के बाद, निम्न खंड रखा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९२३ का १ की धारा ७ में संशोधन।
“ (गक) धारा ३ की उप-धारा (४) के खंड (घ) के अधीन कलक्टर को प्रस्तुत की जानेवाली सुरक्षित जमा की रकम और जिसमें जानकारी प्रस्तुत की जायेगी उसका प्रारूप भी विहित करने के लिए ”।

सन् २०१४ का महा. अध्या क्र. १०। ६. (१) महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क (संशोधन और जारी रहना) अध्यादेश, २०१४ एतद्वारा निरसित किया जाता है। सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. १० का निरसन तथा व्यावृत्ति।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई बात या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या जारी आदेश समेत), इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत की गई, ली गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

सन् १९२३ का १। ७. इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत है राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, निराकरण करने इस अध्यादेश के उपबंधों से अब असंगत कोई ऐसे आदेश दे सकेगी जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो : कठिनाईयों का निराकरण करने की शक्ति।

परंतु, इस अधिनियम में, प्रारंभण की दिनांक से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम, (सन् १९२३ का १), केबल टेलिविजन समेत मनोरंजन के विभिन्न प्रकारों और प्ररूपों पर मनोरंजन शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए उपबंध करता है। उक्त अधिनियम की धारा ३ **अन्य बातों के साथ** राज्य में केबल टेलिविजन पर देय मनोरंजन शुल्क की दरों के लिए उपबंध करता है।

२. केबल टेलिविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, १९९५ (सन् १९९५ का ७), देश में केबल टेलिविजन नेटवर्कों के प्रचालन को विनियमित करता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में चरणबद्धता में सेट टॉप बॉक्स के मार्ग से डिजिटल संबोधित प्रणाली के मार्फत टेलिविजन प्रसारण सौंपा गया है। तदनुसार, महाराष्ट्र राज्य में इन चरणों में अर्थात् ३१ अक्टूबर २०१२ द्वारा मुंबई और मुंबई उपनगरीय जिले के लिए ३१ मार्च, २०१३ द्वारा जिसमें जिन शहरों की जनसंख्या दस लाख से अधिक है और ३१ दिसंबर २०१४ द्वारा राज्य के शेष क्षेत्रों में चरणबद्ध रूप में सेट टॉप बॉक्स के मार्ग से केबल डिजिटलायझेशन किया गया है।

३. चूँकि, डिजिटलायझेशन के बाद सेट टॉप बॉक्स के जरिये, बहु-उद्देशीय प्रणाली ऑपरेटर और केबल ऑपरेटरों की भूमिका व्यापक हुई है, अतः महाराष्ट्र सरकार बहुउद्देशीय प्रणाली ऑपरेटर और केबल ऑपरेटरों को महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम के पुनःरीक्षण के भीतर लाना इष्टकर समझती है, ताकि सरकार को मनोरंजन शुल्क के उद्ग्रहण, वसूली और अदायगी के लिए जिम्मेदार बनाया जा सके उस प्रयोजन के लिए बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम की धाराएँ २, ३ और ७ में संशोधन करने का प्रस्ताव था। उक्त अधिनियम की धारा ५ में संशोधन द्वारा यह भी प्रस्ताव है कि विद्यमान पाँचसौ रुपये से कम नहीं और एक हजार रुपयों से अधिक नहीं वाले जुर्माने की मात्रा को पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं या राजस्व हानि के पाँच गुना, जो भी अधिक हो बढ़ाना है।

४. क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम (सन् १९२३ का १) में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है। अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (सन् २०१४ का महा. अध्यादेश क्र. ४) १० फरवरी २०१४ को प्रख्यापित किया गया था।

५. तत्पश्चात्, २४ फरवरी, २०१४ को राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने पर उक्त अध्यादेश राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिए २४ फरवरी, २०१४ को सन् २०१४ का विधानसभा विधेयक क्रमांक २ महाराष्ट्र विधानसभा में पुरस्थापित किया गया था। तथापि, २८ फरवरी, २०१४ को राज्य विधानमंडल का सत्रावसन होने के कारण उक्त विधेयक पारित नहीं हो सका था। भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश ६ अप्रैल, २०१४ के पश्चात्, प्रवृत्त होने से परिवर्तित होगा। इसलिए, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझा गया है।

६. क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. ४) के प्रवर्तन को जारी रखने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए ५ अप्रैल, २०१४ को महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क (संशोधन और जारी रहना) अध्यादेश, २०१४ (सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. १०) प्रख्यापित हुआ था।

७. प्रस्तुत विधेयक का आशय, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांकित २३ मई २०१४।

बालासाहब थोरात,
राजस्व मंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन ।

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ निम्न प्रस्ताव अन्तर्गस्त है, अर्थात् :—

खण्ड ३.—इस खण्ड के अधीन, महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम की धारा ३ की उप-धारा (४) में निविष्ट किये गये खण्ड (घ) के अनुसार, जिला कलक्टर को बहु-प्रणाली ऑपरेटर या केबल ऑपरेटर द्वारा जुटायी जानेवाली सुरक्षित जमा और जानकारी विहित करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है।

खण्ड ५.—इस खण्ड के अधीन, महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम की धारा ३ की उप-धारा (४) के खण्ड (घ) के अधीन जिला कलक्टर को जुटायी जानेवाली सुरक्षित जमा की रकम और रीति और जिस प्रपत्र में जानकारी जुटायी जायेगी उसे भी विहित करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है।

खण्ड ७.—इस खण्ड के अधीन, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्भूत किसी कठिनाई को राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, दूर करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपर्युक्त प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के हैं।

वित्तिय ज्ञापन ।

प्रस्तुत विधेयक में महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम की धाराएँ २, ३ और ७ में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि केबल ऑपरेटर और बहुउद्देशीय प्रणाली ऑपरेटरों को उक्त अधिनियम के पुनरीक्षण के भीतर लाने की दृष्टि से उन्हें राज्य सरकार को मनोरंजन शुल्क के उद्ग्रहण, वसूली और अदायगी के लिए जिम्मेदार धारक बनाये जाये। उक्त अधिनियम के बेहतर अनुपालन की सुनिश्चिति करने की दृष्टि से, उक्त अधिनियम की धारा ५ में संशोधन द्वारा जुर्माने की मात्रा में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। अतः प्रस्तुत विधेयक में उसके राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में अधिनियमित होने पर राज्य की समेकित निधि में से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(यथार्थ अनुवाद)

ललिता शि. देठे,

भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा।

(महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, आदेश की प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क (संशोधन और जारी रहना) विधेयक, २०१४ ई. पुरःस्थापित करने की अनुशंसा करते हैं।

विधान भवन,

मुंबई,

दिनांकित २ जून २०१४।

डॉ. अनंत कळसे,

प्रधान सचिव,

महाराष्ट्र विधानसभा।